

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

प्रीति राज

बनाम

शिशिर कुमार

2021 का विविध अपील सं. 91

8 अगस्त 2025

(माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. बी. प्रसाद सिंह)

विचार के लिए मुद्दा

क्या अपीलकर्ता-पत्नी हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(आई-ए) तथा धारा 13(1-ए)(ii) के अंतर्गत विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त करने की पात्र हैं?

हेडनोट्स

पक्षकारों के मध्य वैवाहिक संबंध वस्तुतः पूर्णतः समाप्त हो चुका है और यह पुनर्स्थापन योग्य नहीं है, जो कि उत्तरदाता-पति के प्रति अपीलकर्ता-पत्नी द्वारा मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है। (अनुच्छेद - 16)

न्यायालय ने पाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्यों का समुचित परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन नहीं किया गया और अपीलकर्ता-पत्नी की याचिका को अस्वीकार कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय को यह तथ्य ध्यान में रखना चाहिए था कि अपीलकर्ता द्वारा क्रूरता के आधार पर तलाक की याचिका दायर की गई थी, जो मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्यों से सिद्ध हुई है। (अनुच्छेद - 17)

उत्तरदाता-पत्नी ने विवाह विच्छेद की डिक्री प्रदान किए जाने हेतु पर्याप्त आधार प्रस्तुत किया है। (अनुच्छेद - 18)

पत्नी तलाक की डिक्री पारित होने के पश्चात् भी स्थायी भरण-पोषण हेतु धारा 25 के अंतर्गत अलग से कार्यवाही प्रारंभ कर सकती है। अतः तलाक की डिक्री पारित हो जाने के उपरांत भी

न्यायालय का क्षेत्राधिकार समाप्त नहीं होता है और वह स्थायी भरण-पोषण निर्धारित कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालय से यह अपेक्षित है कि वह दोनों पक्षकारों से उनके परिसंपत्तियों और दायित्वों का विवरण प्राप्त करे। (अनुच्छेद - 25, 26)

न्याय दृष्टान्त

जॉयदीप मजूमदार बनाम भारती जैसवाल मजूमदार, (2021) 2 आर. सी. आर. (सिविल) 289; समर घोष बनाम जया घोष, (2007) 4 एस. सी. सी. 511; रजनेश बनाम नेहा, (2021) 2 एस. सी. सी. 324; अदिति उर्फ मिठी बनाम जितेश शर्मा, (2023) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1451; प्रवीण कुमार जैन बनाम अंजू जैन, 2024 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 3678

अधिनियमों की सूची

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955; भारतीय दण्ड विधान, 1860; दहेज निषेध अधिनियम, 1961

मुख्य शब्दों की सूची

मानसिक क्रूरता; दीर्घकालिक पृथक्करण; दांपत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना; विवाह विच्छेदकी डिक्री; स्थायी भरण-पोषण; वैवाहिक विफलता; घरेलू हिंसा; धारा 13(1)(आई-ए); धारा 13(1-ए)(ii); धारा 498-ए भा.दं.वि.; धारा 307 भा.दं.वि.

प्रकरण से उत्पन्न

दिनांक 21.08.2020 को पारित प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, पूर्णिया द्वारा पारित वैवाहिक (तलाक) वाद संख्या 203/2018 के निर्णय एवं डिक्री से उत्पन्न।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता के लिए: श्री करनदीप कुमार, अधिवक्ता

उत्तरदाता के लिए: श्री प्रवीण कुमार अग्रवाल, अधिवक्ता

रिपोर्टर जिनके द्वारा हेडनोट बनाया गया: अमित कुमार मल्लिक, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2021 का विविध अपील सं. 91

=====

प्रीति राज, पति- शिशिर कुमार, पिता- मालानंद मेहता, निवासी बर्धमान हाटा वार्ड सं.14,
अर्जुन भवन जेल चौक के पास, थाना- के. हाट, जिला- पूर्णिया।

... .. अपीलकर्ता/ओं

बनाम

शिशिर कुमार, पिता- सुरेंद्र प्रसाद सिंह, निवासी गोकुल बाबू हाटा खिरु चौक, वार्ड सं. 22,
थाना- के. हाट, जिला-पूर्णिया।

... .. उत्तरदाता/ओं

=====

उपस्थिति:

अपीलकर्ता/ओं के लिए: श्री करणदिप कुमार, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए: श्री प्रवीण कुमार अग्रवाल, अधिवक्ता

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री

एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. बी. प्रसाद सिंह

सी. ए .वी निर्णय

(प्रति: माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. बी. पी. डी. सिंह)

दिनांक: 13-08-2025

पक्षकारों को सुना।

2. वर्तमान अपील हिंदू विवाह अधिनियम, 1984 की धारा 19(1)(1-ए) के तहत दायर की गई है, जिसमें 2018 के वैवाहिक (तलाक) मामला संख्या 203 में विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, पूर्णिया द्वारा पारित 21.08.2020 के निर्णय और डिक्री को चुनौती दी गई है, जिसके तहत अपीलकर्ता-पत्नी द्वारा दायर याचिका, उत्तरदाता-पति के साथ 06.02.2016 को हुए विवाह को रद्द करने के लिए थी, इस याचिका को खारिज कर दिया गया है।

3. परिवार न्यायालय के समक्ष दायर याचिका के अनुसार अपीलकर्ता-पत्नी का मामला यह है कि उत्तरदाता के साथ अपीलकर्ता की शादी हिंदू संस्कारों और अनुष्ठानों के अनुसार 06.02.2016 को हुई थी और विवाह के समय, उसके माता-पिता ने उत्तरदाता को 20 लाख रुपये का उपहार दिया था। विवाह के बाद, अपीलकर्ता ने उत्तरदाता के साथ वैवाहिक जीवन जीना शुरू कर दिया, हालांकि, कुछ समय बाद, उसके ससुराल के सदस्यों ने पूर्णिया शहर में एक चिकित्सा क्लिनिक स्थापित करने के लिए उसके पिता से 20 लाख की अपनी अवैध मांग को पूरा करने के लिए अपीलकर्ता को प्रताड़ित करना और उस पर हमला करना शुरू कर दिया। अंततः, अपीलकर्ता के पिता ने 5 लाख रुपये का ऋण लिया और उन्होंने इसे उत्तरदाता को दे दिया लेकिन फिर से उन्होंने और 15 लाख रुपये के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। यह आरोप लगाया जाता है कि 10.09.2017 को, उत्तरदाता ने अपीलकर्ता को जलाकर मारने का प्रयास किया और रसोई में गैस सिलेंडर खोल दिया, लेकिन किसी तरह उसने अपनी जान बचाई और तब से वह अपने माता-पिता के घर में रह रही है। अपीलकर्ता ने उत्तरदाता और अन्य ससुराल वालों के परिवार के सदस्यों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 498(ए), 120(बी), 307, 511, 34 और दहेज निषेध अधिनियम की

धारा 3/4 के तहत 2017 का पूर्णिया (महिला) थाना कांड संख्या 49 दिनांक 23.09.2017 को दर्ज कराया है। उत्तरदाता ने अपने बचाव के लिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए वैवाहिक वाद संख्या 190/2017 दायर किया है। उत्तरदाता ने उत्तरदाता के खिलाफ 30.01.2018 को 2018 का भरण-पोषण भत्ता मामला संख्या 17 भी दायर किया है जिसमें अपीलकर्ता के भरण-पोषण के रूप में, उत्तरदाता को 15,000/- रुपये प्रति माह का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। अपीलकर्ता ने इस मुद्दे को सुलझाने और उत्तरदाता के साथ एक वैवाहिक जीवन व्यतित करने के लिए अपने सभी प्रयास किए हैं, लेकिन उसके सभी प्रयास विफल हो गए क्योंकि उत्तरदाता, अपीलकर्ता के साथ वैवाहिक संबंध जारी रखने में रुचि नहीं रखता था। इसलिए, अपीलकर्ता ने विवाह विच्छेद के लिए तलाक याचिका दायर की है।

4. वर्तमान मुकदमा दायर करने के बाद, न्यायालय द्वारा उत्तरदाता-पति को समन/अधिसूचना जारी किए गए थे। वह पेश हुए और अपना लिखित बयान दर्ज किया। उत्तरदाता ने अपने लिखित बयान में कहा है कि अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप झूठे और मनगढ़ंत हैं। उत्तरदाता ने कभी भी चिकित्सा क्लिनिक की स्थापना के लिए 20 लाख रुपये की मांग नहीं की है, क्योंकि अपीलकर्ता के साथ विवाह से पहले, उसने अपना क्लिनिक स्थापित कर लिया था। उत्तरदाता ने अपीलकर्ता को अपने वैवाहिक जीवन में वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन यह अपीलकर्ता ही थी जिसे उत्तरदाता के साथ रहने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अंततः, उत्तरदाता ने वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए 2017 का वैवाहिक वाद संख्या 190 दायर किया है। अपीलकर्ता बिना किसी कारण के 10.09.2017 से अपने माता-पिता के घर पर रह रही है। अपीलकर्ता का यह आरोप कि गैस सिलेंडर खोलकर उसे आग लगाने का प्रयास किया गया था, साबित नहीं हुआ है।

5. अपना मामला साबित करने के लिए, अपीलकर्ता ने छह गवाहों, अ.सा. 1 प्रीति राज (अपीलकर्ता), अ.सा. 2 मालानंद महतो (अपीलकर्ता के पिता), अ.सा. 3 अनिल कुमार सिंह, अ.सा. 4 राज कुमार श्रीवास्तव, अ.सा. 5 अनोखे लाल और अ.सा. 6 बिंदेश्वरी महतो को पेश किया है।

6. उत्तरदाता ने भी अपीलकर्ता के मामले को गलत साबित करने के लिए तीन गवाहों को पेश किया है, जो ब.सा. 1 शिशिर कुमार (उत्तरदाता), ब.सा. 2 सुरेंद्र प्रसाद सिंह (अपीलकर्ता के ससुर) और ब.सा. 3 शांति देवी (अपीलकर्ता की सास) हैं।

7. अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य के साथ अपीलकर्ता और उत्तरदाता की ओर से प्रस्तुत किए गए दलीलों और तर्कों को ध्यान में रखते हुए, इस अपील में निर्धारण के लिए मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:-

(i) क्या अपीलकर्ता अपनी अपील में मांगी गई राहत की हकदार है।

(ii) क्या प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, पटना का आक्षेपित निर्णय कानून की दृष्टि से न्यायसंगत, उचित और टिकाऊ है।

8. उपरोक्त दोनों बिंदुओं को दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत तथ्यों और साक्ष्यों और इस मामले में लागू कानून के प्रावधान के आधार पर चर्चा के लिए एक साथ लिया जाता है।

9. यह अपीलकर्ता-पत्नी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि अधिन्स्थ विद्वान न्यायालय ने अपने समक्ष अभिलेख पर रखे गए साक्ष्यों पर विचार किए बिना यांत्रिक तरीके से आदेश पारित किया है। अधिन्स्थ विद्वान न्यायालय यह मानने में विफल रहा है कि उत्तरदाता पक्ष द्वारा अपीलकर्ता को आग लगाकर मारने का प्रयास किया गया था। अपीलकर्ता 10.09.2017 से अपने माता-पिता के घर पर रह रही है लेकिन

उत्तरदाता ने उसे उसके वैवाहिक घर ले जाने का कोई प्रयास नहीं किया है। विद्वान पारिवार न्यायालय यह भी समझने में विफल रहा है कि उत्तरदाता और अन्य ससुराल के परिवार के सदस्यों के खिलाफ दायर आपराधिक मामले में, उत्तरदाता पर भा. दं. वि. की धारा 307 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप पत्र दायर किया गया था जो उत्तरदाता के हाथों क्रूरता के उसके दावे को साबित करता है। अधिन्स्थ विद्वत न्यायालय इस बात पर विचार करने में विफल रही है कि उत्तरदाता-पति मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति है और यह उसके व्यवहार से परिलक्षित होता है और यह एक कारण हो सकता है कि उत्तरदाता की असमर्थता के कारण विवाह पूरा नहीं हो सका।

10. निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले, हमें यह विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि क्या अपीलकर्ता द्वारा क्रूरता के आधार पर दायर तलाक याचिका, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में परिकल्पित आवश्यकताओं को पूरा करती है?

11. हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(आई-ए) के अर्थ के तहत क्रूरता की अवधारणा को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, "जॉयदीप मजूमदार बनाम भारती जैसवाल मजूमदार ", (2021) 2 आर. सी. आर. (सिविल) 289, में निम्नानुसार अवलोकन करके समझाया गया है:-

"10. मानसिक क्रूरता का आरोप लगाने वाले जीवनसाथी के कहने पर, विवाह विच्छेद पर विचार करने के लिए, इस तरह की मानसिक क्रूरता का परिणाम ऐसा होना चाहिए कि यह वैवाहिक संबंध को जारी रखना संभव नहीं है। दूसरे शब्दों में, पीड़ित पक्ष से इस तरह के आचरण को माफ करने और अपने जीवनसाथी के साथ रहने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। सहिष्णुता का स्तर एक जोड़े से दूसरे में भिन्न होगा और न्यायालय को, शिक्षा के स्तर और पक्षों की स्थिति की पृष्ठभूमि को भी ध्यान में रखना होगा, ताकि यह

निर्धारित किया जा सके कि क्या पीड़ित पक्ष के कहने पर कथित क्रूरता विवाह के विघटन को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त है..."

12. "समर घोष बनाम जया घोष", (2007) 4 एस. सी. सी. 511, मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उदाहरणात्मक मामले दिए जहां मानसिक क्रूरता का निष्कर्ष निकाला जा सकता है, इस बात पर जोर देते हुए कि कोई समान मानक निर्धारित नहीं किया जा सकता है और प्रत्येक मामले का निर्णय अपने तथ्यों पर करना होगा।

"85. मार्गदर्शन के लिए कभी भी एक समान मानक निर्धारित नहीं किया जा सकता है, फिर भी हम मानव व्यवहार के कुछ उदाहरणों को गिनना उचित समझते हैं जो 'मानसिक क्रूरता' के मामलों से निपटने में प्रासंगिक हो सकते हैं। बाद के अनुच्छेदों में बताए गए उदाहरण केवल उदाहरणात्मक हैं और संपूर्ण नहीं हैं।

(i) पक्षों के पूर्ण वैवाहिक जीवन पर विचार करने पर, तीव्र मानसिक पीड़ा, वेदना और कष्ट जो पक्षों के लिए एक-दूसरे के साथ रहना असंभव बनाती है, मानसिक क्रूरता के व्यापक मानकों के अंतर्गत आ सकती है।

(ii) पक्षों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन के व्यापक मूल्यांकन पर, यह बहुत स्पष्ट हो जाता है कि स्थिति ऐसी है कि पीड़ित पक्ष को इस तरह के आचरण को सहन करने और दूसरे पक्ष के साथ रहने के लिए उचित रूप से नहीं कहा जा सकता है।

(iii) केवल उदासीनता या स्नेहाभाव को क्रूरता नहीं माना जा सकता, परंतु बार-बार कठोर भाषा का प्रयोग, चिड़चिड़ा आचरण, उपेक्षा एवं निरंतर

असंवेदनशीलता इस सीमा तक पहुँच सकती है कि वह दूसरे जीवनसाथी के लिए वैवाहिक जीवन को पूर्णतः असहनीय बना दे।

(iv) मानसिक क्रूरता एक मानसिक अवस्था है। एक जीवनसाथी में दूसरे जीवनसाथी के आचरण के कारण लंबे समय तक गहरी पीड़ा, निराशा, हताशा की भावना मानसिक क्रूरता का कारण बन सकती है।

(v) लगातार अपशब्दयुक्त और अपमानजनक व्यवहार का सिलसिला, जो जीवनसाथी को यातना देने, असुविधा पहुँचाने या उसके जीवन को कष्टमय बनाने के लिए किया जाता है।

(vi) एक जीवनसाथी का निरंतर अनुचित आचरण और व्यवहार वास्तव में दूसरे जीवनसाथी के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। शिकायत किया गया व्यवहार और परिणामी खतरा या आशंका बहुत गंभीर, पर्याप्त और भारी होना चाहिए।

(vii) निरंतर निंदनीय आचरण, योजनाबद्ध उपेक्षा, उदासीनता या दांपत्य सौहार्द्र के सामान्य मानक से पूर्ण विचलन, जिससे मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचता है या परपीडक आनंद प्राप्त होता है, भी मानसिक क्रूरता के बराबर हो सकता है।

(viii) आचरण ईर्ष्या, स्वार्थ, स्वामित्व से बहुत अधिक होना चाहिए, जो नाखुशी और असंतोष का कारण बनता है और भावनात्मक परेशानी मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक देने का आधार नहीं हो सकती है।

(ix) केवल मामूली चिड़चिड़ापन, झगड़े, वैवाहिक जीवन का सामान्य पतन जो दिन-प्रतिदिन के जीवन में होता है, मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक देने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

(x) वैवाहिक जीवन की समीक्षा समग्र रूप से की जानी चाहिए और वर्षों की अवधि में कुछ अलग-थलग मामले क्रूरता के बराबर नहीं होंगे। दुर्व्यवहार काफी लंबी अवधि के लिए निरंतर होना चाहिए, जहां संबंध इस हद तक बिगड़ गए हैं कि पति या पत्नी के कृत्यों और व्यवहार के कारण, पीड़ित पक्ष को अब दूसरे पक्ष के साथ रहना बेहद मुश्किल लगता है, जो मानसिक क्रूरता के बराबर हो सकता है।

(xi) यदि कोई पति बिना चिकित्सा कारणों के और अपनी पत्नी की सहमति या जानकारी के बिना नसबंदी के ऑपरेशन के लिए खुद को प्रस्तुत करता है और इसी तरह यदि पत्नी चिकित्सा कारण के बिना या अपने पति की सहमति या जानकारी के बिना नसबंदी या गर्भपात कराती है, तो जीवनसाथी का ऐसा कार्य मानसिक क्रूरता का कारण बन सकता है।

(xii) बिना किसी शारीरिक अक्षमता या वैध कारण के काफी समय तक संभोग करने से इनकार करने का एकतरफा निर्णय मानसिक क्रूरता के बराबर हो सकता है।

(xiii) विवाह के बाद पति या पत्नी में से किसी का भी विवाह से संतान न होने का एकतरफा निर्णय क्रूरता हो सकता है।

(xiv) जहां निरंतर अलगाव की एक लंबी अवधि रही है, यह उचित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वैवाहिक बंधन सुधार से परे है। विवाह

यद्यपि विधिक बंधन से समर्थित होता है, तथापि वह केवल एक औपचारिक या काल्पनिक संबंध बनकर रह जाता है। उस बंधन को तोड़ने से इनकार करने से, ऐसे मामलों में कानून, विवाह की पवित्रता की रक्षा नहीं करता है; इसके विपरीत, यह पक्षों की भावनाओं और संवेदनओं के प्रति बहुत कम सम्मान दिखाता है। ऐसी स्थितियों में, यह मानसिक क्रूरता का कारण बन सकता है..."

13. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त सिद्धांत के आधार पर, जब हम पक्षों की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आलोक में वर्तमान मामले की जांच करते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि पक्षों के बीच लंबे समय से अलगाव है और वैवाहिक बंधन वस्तुतः सुधार से परे है और इस परिस्थिति में, यदि तलाक नहीं दिया जाता है, तो यह विवाह की पवित्रता को नष्ट कर देगा।

14. विचारण न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह पता चलता है कि पक्षों के बीच कई सारे मामले चल रहे थे। ऐसा भी प्रतीत होता है कि 2017 का पूर्णिया (महिला) थाना कांड संख्या 49 अपीलकर्ता-पत्नी द्वारा भा. दं. वि. की धारा 498(ए), 120, 307, 511, 34 के तहत दायर किया गया था जिसमें भा. दं. वि. की धारा 498(ए) के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है। यह भी प्रतीत होता है कि 2017 का वैवाहिक मुकदमा संख्या 190 पति द्वारा वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए दायर किया गया था जिसमें डिक्री पारित की गई थी, लेकिन इसके बावजूद अपीलकर्ता-पत्नी अपने पति के साथ नहीं आई। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1-ए)(ii) के तहत तलाक के लिए डिक्री पारित करने के लिए यह अपने आप में पर्याप्त आधार है।

15. हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9, 13, 13 ए और 14 के प्रासंगिक भागों को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा, जो इस प्रकार हैं:-

"9. वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना - जब पति या पत्नी में से कोई भी, बिना किसी उचित कारण के, दूसरे के से अलग हो जाता है, तो पीड़ित पक्ष, जिला न्यायालय में याचिका द्वारा, वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए आवेदन कर सकता है और न्यायालय, ऐसी याचिका में दिए गए बयानों की सच्चाई से संतुष्ट होने पर और यह कि ऐसा कोई कानूनी आधार नहीं है कि आवेदन स्वीकार न किया जाए, तदनुसार वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना का आदेश दे सकता है।

स्पष्टीकरण - जहाँ यह प्रश्न उत्पन्न होता है, कि क्या एक दूसरे से अलग होने का कोई उचित कारण था, उचित कारण साबित करने का बोझ उस व्यक्ति पर होगा जो दूसरे से अलग हो गया है।

13. तलाक (1) इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले या बाद में संपन्न कोई भी विवाह, पति या पत्नी में से किसी एक द्वारा प्रस्तुत याचिका पर, इस आधार पर तलाक की डिक्री द्वारा भंग किया जा सकता है कि दूसरा पक्ष

-

(i) विवाह सम्पन्न हो जाने के बाद, अपने पति या पत्नी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ स्वेच्छा से संभोग किया है; या (i ए) विवाह संपन्न होने के बाद, याचिकाकर्ता के साथ क्रूरता का व्यवहार किया है; या (i बी) याचिका प्रस्तुत करने से तुरंत पहले कम से कम 2 साल की निरंतर अवधि के लिए याचिकाकर्ता को परित्याग दिया है; या

(ii).....

स्पष्टीकरण - इस उप-धारा में, "परित्याग" पद का अर्थ है याचिकाकर्ता का दूसरे पक्ष द्वारा उचित कारण के बिना परित्याग और ऐसे पक्ष की सहमति के बिना या इच्छा के विरुद्ध, और इसमें विवाह के दूसरे पक्ष द्वारा याचिकाकर्ता की जानबूझकर उपेक्षा शामिल है, और इसके व्याकरणिक रूपांतरों और सजातीय अभिव्यक्तियों का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा।

(1क) विवाह का कोई भी पक्ष, चाहे वह इस अधिनियम के लागू होने से पहले या बाद में संपन्न हुआ हो, इस आधार पर तलाक की डिक्री द्वारा विवाह विच्छेद के लिए याचिका भी प्रस्तुत कर सकता है -

(i) जिस कार्यवाही में वे पक्षकार थे, उस कार्यवाही में न्यायिक अलगाव के लिए डिक्री पारित होने के बाद एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए विवाह के पक्षों के बीच सहवास फिर से शुरू नहीं हुआ है; या

(ख) कि विवाह के पक्षकारों के बीच एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि तक सहवास की कोई पुनर्स्थापना नहीं हुई है, न्यायिक पृथक्करण के लिए डिक्री पारित होने के बाद, जिस कार्यवाही में वे पक्षकार थे; या

.....

13 ए. तलाक की कार्यवाही में वैकल्पिक राहत - इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी कार्यवाही में, तलाक की डिक्री द्वारा विवाह विच्छेद के लिए याचिका पर, सिवाय इसके कि याचिका धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ii), (vi) और (vii) में उल्लिखित आधारों पर आधारित हो, न्यायालय, यदि वह मामले की परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा करना उचित समझता है, तो इसके बजाय न्यायिक पृथक्करण की डिक्री पारित कर सकता है।

14. विवाह के एक वर्ष के भीतर विवाह विच्छेद के लिए कोई याचिका प्रस्तुत नहीं की जानी चाहिए- (1) इस अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद, यह किसी भी न्यायालय के लिए विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह विच्छेद के लिए किसी भी याचिका पर विचार करने के लिए सक्षम नहीं होगा, जब तक कि याचिका प्रस्तुत करने की तिथि को विवाह की तिथि से एक वर्ष बीत चुका हो।

16. इसके अलावा, यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता-पत्नी अपने पति के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है, जैसा कि उत्तरदाता द्वारा वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए दायर 2017 के वैवाहिक वाद संख्या 190 में भी दिखाई देता है, जिसमें वह ओ. पी. डब्ल्यू. 1 के रूप में पेश हुई है और अनुच्छेद 18 में अपना साक्ष्य प्रस्तुत किया है और वर्तमान मामले में भी, उसकी अ.सा. 1 के रूप में जांच की गई है और अनुच्छेद 49 में अपना साक्ष्य प्रस्तुत किया है। इसलिए, अपीलकर्ता-पत्नी के उपरोक्त साक्ष्यों के साथ-साथ अपीलकर्ता-पत्नी द्वारा अपने पति (उत्तरदाता) के खिलाफ दायर आपराधिक मामलों की पृष्ठभूमि में, यह स्पष्ट है कि दोनों पक्षों के बीच वैवाहिक बंधन वस्तुतः टूट गया है और यह सुधार से परे है जो अपीलकर्ता द्वारा अपने पति (उत्तरदाता) के प्रति मानसिक क्रूरता के दायरे में आता है।

17. इसलिए, मामले के अभिलेख का अवलोकन करने और अपीलकर्ता और उत्तरदाता की ओर से विद्वान अधिवक्ता की ओर से पेश की गई दलीलों पर विचार करने के बाद और अपीलकर्ता-पत्नी द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेख पर साक्ष्य का पूरी तरह से विश्लेषण करने के बाद, इस न्यायालय ने पाया कि अधिन्स्थ विद्वान न्यायालय ने अपने सही परिप्रेक्ष्य में साक्ष्य की सराहना नहीं की है और अपीलकर्ता-पत्नी की याचिका को खारिज कर दिया है। अधिन्स्थ न्यायालय को इस तथ्य पर विचार करना चाहिए था कि तलाक याचिका अपीलकर्ता द्वारा क्रूरता के आधार पर दायर की गई थी जो मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के

बल पर साबित हुई है। अपीलकर्ता और उत्तरदाता के बीच का वैवाहिक संबंध पहले ही टूट चुका है और उनके वैवाहिक जीवन की पुनर्स्थापना की कोई उम्मीद नहीं है।

18. आगे की चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उत्तरदाता-पत्नी ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1-ए)(ii) में उल्लिखित आधार पर विवाह के विघटन की डिक्री देने के लिए एक आधार बनाया है।"

19. इस मामले के मद्देनजर, 2018 के वैवाहिक तलाक मामला संख्या 203 में विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, पूर्णिया द्वारा पारित दिनांक 21.08.2020 के आक्षेपित निर्णय को इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(1-ए) के तहत उत्तरदाता के साथ, तलाक की डिक्री द्वारा विवाह विच्छेद के लिए, अपीलकर्ता-पत्नी की प्रार्थना की अनुमति है और उत्तरदाता-पति के साथ अपीलकर्ता-पत्नी का विवाह तलाक की डिक्री द्वारा भंग कर दिया जाता है।

20. रजिस्ट्री को तदनुसार तलाक की डिक्री तैयार करने का निर्देश दिया जाता है।

21. इस आदेश के जारी करने से पहले, हमें अपीलकर्ता को दिए जाने वाले स्थायी गुजारा भत्ते की राशि पर अपनी राय देनी होगी।

22. यहाँ 1955 के अधिनियम की धारा 25 का उल्लेख करना उपयोगी है, जो इस प्रकार है:

"धारा 25। स्थायी गुजारा भत्ता और भरण-पोषण: (1) इस अधिनियम के तहत अधिकारिता का प्रयोग करने वाला कोई भी न्यायालय, कोई डिक्री पारित करते समय या उसके बाद किसी भी समय, यथास्थिति, पत्नी या पति द्वारा इस उद्देश्य के लिए किए गए आवेदन पर, आदेश दे सकता है कि उत्तरदाता

अपीलकर्ता को उसके या उसके भरण-पोषण के लिए भुगतान करेगा और आवेदक के जीवन से अधिक अवधि के लिए ऐसी सकल राशि या ऐसी मासिक या आवधिक राशि का समर्थन करेगा जो उत्तरदाता की अपनी आय और अन्य संपत्ति, यदि कोई हो, तो आवेदक की आय और अन्य संपत्ति (पक्षों के आचरण और मामले की अन्य परिस्थितियों) को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय को न्यायसंगत प्रतीत होता हो, और ऐसा कोई भी भुगतान, यदि आवश्यक हो, तो उत्तरदाता की अचल संपत्ति पर शुल्क द्वारा सुरक्षित किया जा सकता है।”

23. 1955 के अधिनियम की धारा 25 में प्रयुक्त भाषा के आलोक में, यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत दावा आवेदन पर ही किया जाना चाहिए जिसमें उसकी अपनी आय या अन्य संपत्ति के बारे में सभी विवरण प्रस्तुत किए गए हों। इसके अतिरिक्त, दूसरे पक्ष को अपना बचाव प्रस्तुत करने का अवसर भी दिया जाना चाहिए।

24. भरण-पोषण की राशि प्रत्येक मामले के लिए व्यक्तिपरक है और विभिन्न परिस्थितियों और कारकों पर निर्भर है। न्यायालय को दोनों पक्षों की आय; विवाह के निर्वाह के दौरान आचरण; उनकी व्यक्तिगत सामाजिक और वित्तीय स्थिति; प्रत्येक पक्ष के व्यक्तिगत खर्च; अपने आश्रितों को बनाए रखने के लिए उनकी व्यक्तिगत क्षमताओं और कर्तव्यों; विवाह के निर्वाह के दौरान पत्नी द्वारा आनंदित जीवन की गुणवत्ता; विवाह की अवधि और ऐसे अन्य समान कारकों जैसे कारकों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। स्थायी गुजारा भत्ता के अनुदान का निर्देश दोनों पक्षों की सामाजिक, वित्तीय स्थिति का आकलन करने के बाद और पति या पत्नी पर पड़ने वाले दायित्वों के बोझ को रजनेश बनाम नेहा, (2021) 2 एस. सी. सी. 324, में प्रतिवेदित, मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में समझने के बाद दिया जाना चाहिए, जिसे अदिति उर्फ मिठी बनाम जितेश शर्मा, (2023) एस. सी. सी.

ऑनलाइन एस. सी. 1451, में प्रतिवेदित, के साथ पढ़ा गया, जिसे प्रवीण कुमार जैन बनाम अंजू जैन, 2024 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 3678, में प्रतिवेदित, के साथ पढ़ा गया।

25. जो भी हो, 1955 के अधिनियम की धारा 25 में ही यह परिकल्पना की गई है कि पत्नी तलाक की डिक्री के बाद भी स्थायी गुजारा भत्ता के अनुदान के लिए कार्यवाही शुरू कर सकती है। इसलिए, डिक्री पारित होने के साथ ही न्यायालय अपने अधिकार से विमुक्त (functus officio) नहीं हो जाता और उसके बाद भी गुजारा भत्ता देने का अधिकार उसके पास बना रहता है।

26. तदनुसार, हम स्थायी गुजारा भत्ता की राशि तय करने के संबंध में ही मामले को विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, पूर्णिया को वापस भेजना उपयुक्त और उचित समझते हैं। अधिन्स्थ न्यायालय से उम्मीद की जाती है कि वह अपीलकर्ता-पत्नी और उत्तरदाता-पति को रजनेश बनाम नेहा, (2021) 2 एस. सी. सी. 324, में प्रतिवेदित, जिसे अदिति उर्फ मिठी बनाम जितेश शर्मा, (2023) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1451, में प्रतिवेदित, के साथ पढ़ा गया, जिसे प्रवीण कुमार जैन बनाम अंजू जैन, 2024 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 3678, में प्रतिवेदित, के साथ पढ़ा गया, मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में उनकी संपत्ति और दायित्वों के बारे में विवरण दाखिल करने का निर्देश देगा और उनकी संपत्ति और दायित्वों का विश्लेषण करते हुए, निर्णय पारित होने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर स्थायी गुजारा भत्ता के संबंध में उचित आदेश पारित करें। दोनों पक्षों को उपरोक्त मामले के शीघ्र निपटारे में सहयोग करने का निर्देश दिया गया है। किसी भी पक्ष के उपस्थित न होने की स्थिति में, कानून के अनुसार उचित आदेश पारित किया जाएगा।

27. यह स्पष्ट किया जाता है कि 15,000/- रुपये प्रति माह का अंतरिम भरण-पोषण, जो 2018 के भरण-पोषण मामला संख्या 17(एम) में विद्वान परिवार न्यायालय

द्वारा अपीलकर्ता-पत्नी को दिया गया था, स्थायी गुजारा भत्ता तय होने तक उत्तरदाता-पति द्वारा भुगतान किया जाएगा।

28. उपरोक्त चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, 2021 की एम. ए. संख्या 91 का निपटारा किया जाता है।

29. लंबित आई. ए. (ओं), यदि कोई हो, तो निपटाया जा सकता है।

(एस. बी. प्रसाद सिंह, न्यायमूर्ति)

(पी. बी. भजंत्री, न्यायमूर्ति)

शागीर/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।